

प्रेस विज्ञप्ति

जामिया लॉ फैकल्टी के छात्रों ने विकसित भारत@2047 के पर किया विचार-मंथन

विधि संकाय के छात्रों ने विकसित भारत@2047 के रोडमैप पर चर्चा के लिए जामिया मिल्लिया इस्लामिया के एफटीके-सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र में एक बहुत ही आकर्षक सत्र का आयोजन किया। 11 दिसंबर 2023 को, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए 'विकसित भारत@2047: वॉयस ऑफ यूथ' लॉन्च किया। यह कार्यक्रम भारत की आजादी के 100वें वर्ष के अवसर पर 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलने के मुख्य दृष्टिकोण के साथ शुरू किया गया है।

यह व्यापक दृष्टिकोण विकास के विभिन्न आयामों को शामिल करता है, जिनमें शामिल हैं- निरंतर और समावेशी आर्थिक विकास प्राप्त करने पर केंद्रित आर्थिक विकास; समग्र सामाजिक विकास और समावेशिता के लक्ष्य वाली सामाजिक प्रगति; और पर्यावरणीय स्थिरता, जिम्मेदार पर्यावरणीय प्रथाओं और सुशासन पर जोर देना जो प्रभावी और पारदर्शी शासन के लिए प्रयास करता है।

विधि संकाय के कई छात्र- सहर रऊफ, जान्हवी रस्तोगी, ज़ोया शब्बीर [बीए, एलएलबी (ऑनर्स) अंतिम वर्ष], रशिका अख्तर, मुहम्मद शागिल अंसारी, वाफ़िया फ़ैज़ और अबू बकर [बीए, एलएलबी। (ऑनर्स) प्रथम वर्ष] ने विधि संकाय के प्रोफेसर डॉ. फैज़ानुर रहमान द्वारा निर्देशित विकसितभारत@2047 से संबंधित प्रश्नों पर अपने विचार प्रस्तुत किए।

2047 में, विकसित भारत को एक ऐसे देश की तरह दिखना चाहिए जहां इसकी बुनियादी से लेकर उन्नत सुविधाएं मानसिक और शारीरिक रूप से दिव्यांग लोगों सहित सभी के लिए सुलभ और सस्ती हों। किसी भी प्रकार के धर्म और जाति-आधारित असमानता और भेदभाव का उन्मूलन होना चाहिए। इसके अलावा, भारत को विभिन्न क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मशीन लर्निंग को शामिल करते हुए एक कार्बन-नेगेटिव और तकनीकी रूप से उन्नत देश होना चाहिए। भारतीय नागरिकों की क्रय-शक्ति समानता बेहतर होनी चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप सभी नागरिकों का जीवन स्तर ऊंचा होगा।

छात्रों ने शिक्षा और शैक्षिक अवसरों के मानक और गुणवत्ता को बढ़ाने और व्यक्तियों के कौशल विकास के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के अधिक से अधिक विविध रूपों को पेश करने की आवश्यकता व्यक्त की। युवाओं के संचार कौशल, व्यक्तित्व विकास और आत्मविश्वास निर्माण की समग्र उन्नति पर भी जोर दिया जाना चाहिए ताकि वे अपनी राय व्यक्त करने में सक्षम हों। इसके अलावा, भारत में तमिलनाडु की तरह एक बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है, जो एक अखिल भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम के माध्यम से किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, भारत को अपना स्वयं का व्यापक एआई अधिनियम बनाने का लक्ष्य रखना चाहिए, ताकि लोग इसके कामकाज को विनियमित कर सकें।

विकसित भारत@2047 को एक संभावना बनाने के लिए, सबसे पहले, सरकार व्यक्तिगत स्तर पर जागरूकता का प्रसार सकती है और साथ ही जमीनी स्तर पर काम करने के लिए अभियानों, शैक्षिक मेलों और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से गैर सरकारी संगठनों और नागरिक सामाजिक संगठनों के सहयोग से जागरूकता फैला सकती है। तकनीकी प्रगति में लगातार वृद्धि के साथ, छात्र इस उद्देश्य के

लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं, साथ ही समाज के हाशिये पर और वंचित वर्गों के संघर्षों को उजागर करने के लिए यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह संसद में हमारे प्रतिनिधियों तक पहुंचे ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

छात्र युवाओं की सक्रिय भागीदारी के बिना एक विकसित राष्ट्र की कल्पना करने पर सहमत हुए। इसलिए, विधि संकाय के छात्रों द्वारा किया गया यह अभ्यास, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा साझा किए गए दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए, विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है।

जनसंपर्क कार्यालय
जामिया मिल्लिया इस्लामिया